

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट एवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 20 जून से 28 जून 2026

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

वर्ष- 13

अंक-97

पृष्ठ- 8

मूल्य- रु. 5/-

जी7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण संबोधन: संतुलित और टिकाऊ आर्थिक विकास पर दिया जोर

भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत, सस्टेनेबल ग्रोथ और डिजिटल इकोनॉमी में नए अवसर

नई दिल्ली: जी7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “Reviving a Balanced, Shared and Sustainable Economic Growth for All” विषय पर महत्वपूर्ण संबोधन दिया। उन्होंने वैश्विक स्तर पर समावेशी, संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, भू-राजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने जलवायु वित्त, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और बहुपक्षीय संस्थाओं के सुधार पर विशेष ध्यान देने की बात कही। भारत की ओर से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को साझा किया गया।

प्रधानमंत्री के इस संबोधन से भारत की वैश्विक छवि और मजबूत हुई है। सस्टेनेबल और समावेशी विकास पर फोकस से ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट टेक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशक रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत की नीतिगत स्थिरता और सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। निवेशक जी7 देशों के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक सहयोग और नीतिगत फैसलों पर नजर रखें।



ट्रम्प टैरिफ के बावजूद मध्य प्रदेश का निर्यात 4% बढ़ा: चीन-दक्षिण अफ्रीका में बढ़ी मांग से मिली राहत

निर्यात वृद्धि से औद्योगिक विकास को गति, नए बाजारों की खोज से स्थिरता और अवसर

भोपाल: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद मध्य प्रदेश का निर्यात 4 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य के निर्यात में यह वृद्धि मुख्य रूप से चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे नए बाजारों में बढ़ती मांग के कारण संभव हुई है।

मध्य प्रदेश से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। ट्रम्प टैरिफ से अमेरिकी बाजार में दबाव बढ़ने के बावजूद राज्य ने अपने निर्यात गंतव्यों में विविधता लाकर नुकसान की भरपाई कर ली है। चीन और दक्षिण अफ्रीका में मांग बढ़ने से राज्य के निर्यातकों को नया बाजार मिला है।

यह आंकड़ा मध्य प्रदेश की औद्योगिक और निर्यात क्षमता के लिए सकारात्मक संकेत है। ट्रम्प टैरिफ जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद राज्य का निर्यात बढ़ना दर्शाता है कि यहां के उद्योग लचीले और अनुकूलनीय हैं। निवेशक फार्मा, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर पर ध्यान दे सकते हैं। पीथमपुर, इंदौर और भोपाल

जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में निर्यात आधारित इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। लंबी अवधि के निवेशक मध्य प्रदेश को निर्यात हब के रूप में देख सकते हैं। सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीतियां और नए बाजारों की खोज से राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। निवेशक निर्यात आंकड़ों और वैश्विक व्यापार नीतियों पर नजर रखें।

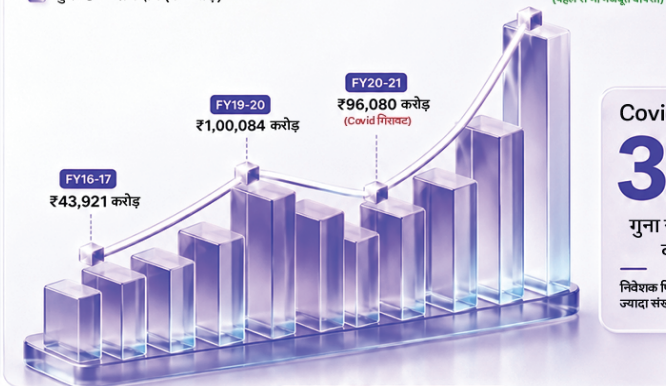


बाजार गिरा, घबराहट बढ़ी?

उतार-चढ़ाव निवेश का एक हिस्सा है।

भारत में पिछले 10 सालों में SIP निवेश में बढ़ोतरी

कुल SIP योगदान (₹ करोड़)



Covid के बाद
3X
गुना से अधिक
बढ़त
निवेशक फिर लौटे और
ज्यादा संख्या में।

यह क्या दिखाता है?



बाजार ने वापसी की



SIP जारी रही



निवेशक टिके रहे



उतार-चढ़ाव ने SIPs नहीं रोकी

उतार-चढ़ाव के बीच निरंतरता अक्सर निवेशकों का साथ देती है।



रुको मत। आगे बढ़ो।

* म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। | Source: AMFI



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com



PM Modi Distributes ₹2,400 Crore Under Vikasit Bharat Rozgar Yojana

Major Push for Job Creation: Incentives to Accelerate Employment Across Manufacturing and Services Sectors

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi distributed approximately ₹2,400 crore as incentives under the Prime Minister Vikasit Bharat Rozgar Yojana. The disbursement, aimed at boosting employment generation, was carried out during a special event in New Delhi. The scheme provides financial incentives to companies that create new jobs, with a special focus on manufacturing, services, and labour-intensive sectors. Officials said the incentives would directly support the creation of lakhs of new employment opportunities, particularly benefiting youth and first-time job seekers. The government has positioned the scheme as a key initiative under its broader vision

of building a developed India. The event saw participation from industry representatives and beneficiaries who received the incentives. Government sources indicated that the scheme has been designed to encourage companies to expand hiring while supporting formalisation of the workforce. The disbursement is viewed positively for sectors aligned with employment generation, including manufacturing, textiles, electronics, and services. Companies receiving incentives under such schemes often see improved margins and expansion capacity, which can translate into stronger long-term

performance. Investors tracking the employment and manufacturing theme can consider selective exposure to companies likely to benefit from government-linked incentive programmes. While near-term market reaction may be limited, sustained policy support for job creation is expected to support broader economic momentum over the medium term.



भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू: द्विपक्षीय व्यापार को मिलेगा नया बढ़ावा निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर: निर्यातकों को टैरिफ राहत, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में तेजी की उम्मीद

नई दिल्ली: भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) 15 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। भारत के लिए यह एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार है। इस FTA के तहत कई उत्पादों पर टैरिफ में कटौती या पूरी तरह छूट मिलेगी। भारत के टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और कृषि उत्पादों को ब्रिटेन में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। वहीं ब्रिटेन को भारत में कुछ क्षेत्रों में आसान प्रवेश मिलेगा। दोनों देशों के बीच सेवाओं के व्यापार में भी वृद्धि होने की संभावना है, खासकर आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज में।

यह एग्रीमेंट भारतीय निर्यातकों और निवेशकों के लिए सकारात्मक विकास है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के निर्यात उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। लंबी अवधि के निवेशक टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर पर ध्यान दे सकते हैं। FTA से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने से लॉजिस्टिक्स, सप्लाय चैन और संबंधित क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा होंगे। निवेशक इस एग्रीमेंट के तहत आने वाले उत्पादों और सेवाओं पर नजर रखें। कुल मिलाकर यह समझौता भारत-ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और निवेशकों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा।



रिलायंस जियो IPO की तैयारी: AGM से पहले ₹38,000 करोड़ का मेगा IPO ला सकती है कंपनी निवेशकों के लिए बड़ा मौका: डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग, लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदारी का अवसर

नई दिल्ली: रिलायंस जियो अपने आईपीओ को एजीएम से पहले लाने की तैयारी में है। कंपनी ₹38,000 करोड़ का बड़ा आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। यदि यह आईपीओ होता है तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और 5जी, फाइबर, डिजिटल सर्विसेज और रिटेल के साथ एक मजबूत इकोसिस्टम बना चुकी है। आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का उपयोग नेटवर्क विस्तार, नई टेक्नोलॉजी और कर्ज कम करने में किया जा सकता है। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को भी मूल्य अनलॉक होने का फायदा मिल सकता है।

जियो का संभावित मेगा आईपीओ निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। डिजिटल इंडिया, 5जी और डेटा खपत की बढ़ती मांग को देखते हुए जियो की लंबी अवधि की ग्रोथ संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। निवेशक इस आईपीओ पर नजर रखें और कंपनी के वैल्यूएशन, यूजर्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दें। हालांकि आईपीओ का आकार बढ़ा होने से शुरुआती दिनों में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदारी का अच्छा मौका दे सकता है। निवेशक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार फैसला लें।



Bhopal Gears Up for GIS-2027: Second Global Investors Summit Aims to Break All Previous Records

Massive Investment Push: Madhya Pradesh Eyes Record-Breaking Commitments in Manufacturing, Green Energy and Infrastructure

New Delhi: Bhopal is preparing to host the second edition of the Global Investors Summit (GIS-2027), with the state government setting an ambitious target to surpass the investment pledges secured in the previous summit. The upcoming summit is expected to attract significantly higher commitments across key sectors including manufacturing, renewable energy, logistics, information technology, and agro-processing.

The state administration has already begun intensive preparations, including infrastructure upgrades in Bhopal, policy refinements, and targeted outreach to domestic and international investors. Special focus is being placed on emerging areas such as electric vehicles, green hydrogen, data centres, and semiconductor-related ancillary

industries. The government aims to leverage Madhya Pradesh's strategic location, improving connectivity through expressways and rail corridors, and availability of industrial land to position the state as a preferred investment destination.

GIS-2027 is also expected to showcase Madhya Pradesh's progress in ease of doing business, single-window clearance systems, and sector-specific incentives. The previous summit had generated substantial investment proposals, and the state is now looking to convert those into actual ground-level projects while attracting fresh capital.

The upcoming Global Investors Summit presents a strong opportunity for both domestic and foreign investors. Madhya Pradesh offers competitive advantages

in terms of lower operational costs, growing skilled workforce, and improving logistics infrastructure. Sectors such as manufacturing, renewable energy, logistics, and food processing are likely to receive focused policy support during the summit.

Long-term investors can consider Madhya Pradesh as an emerging industrial hub with multi-year growth potential. However, they should closely monitor the actual conversion of investment proposals into projects, policy execution, and sector-specific incentives announced during GIS-2027. The summit is expected to provide greater clarity on the state's investment roadmap for the next five years.

Slow and Steady Builds the Wealth
Speed Isn't Everything

Keep Moving Ahead

Recovery Slowly

Market Goes Down

Quick Gains

We All Know Who Wins in the End

Stay invested. Stay ahead.

*Mutual funds are subject to market risk

क्या आपका बैकअप तैयार है?
निवेश के साथ सुरक्षा भी जरूरी है

इमरजेंसी फंड

निवेश को समय से पहले तोड़ने से बचाए

बढ़त से पहले स्थिरता बनाए

वित्तीय तनाव कम करे

अचानक आने वाले खर्चों में सहायता बने

मुश्किल समय में निवेश जारी रखने में मदद करे

क्या आपके पास सुरक्षा कवच है?



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com



NFO Alert: Kotak Mutual Fund Launches First SIF with Hybrid Long-Short Strategy

New Category Opens Doors for Sophisticated Investors: Long-Short Approach Aims at Risk-Adjusted Returns in Volatile Markets

Mumbai: Kotak Mutual Fund has launched its first Specialized Investment Fund (SIF) featuring a hybrid long-short strategy. This marks the entry of Kotak MF into the newly introduced SIF category, which offers greater flexibility compared to traditional mutual funds.

The fund aims to generate returns by taking long positions in fundamentally strong stocks and sectors while simultaneously taking short positions in overvalued or weak stocks. This hybrid approach seeks to deliver relatively stable risk-adjusted returns with lower correlation to overall market movements. The strategy is designed to perform across different market cycles, including volatile or sideways markets.

SIFs allow fund managers higher limits on derivatives usage and short selling, enabling more sophisticated investment

techniques. The Kotak SIF will primarily focus on equity and equity-related instruments with a dynamic allocation between long and short positions based on market conditions and stock-specific opportunities.

This launch adds a new layer of product choice for investors looking beyond conventional long-only equity or debt funds. The hybrid long-short strategy can serve as a diversification tool within a larger portfolio, potentially reducing overall volatility while still offering equity-like return potential.

However, SIFs are generally suited for investors with a higher risk appetite and understanding of derivative-based strategies. They typically come with higher minimum investment requirements and may carry relatively higher costs compared to regular mutual

funds. Investors should carefully assess their risk tolerance and investment horizon before participating in the NFO.

Long-term investors seeking alternative strategies to navigate uncertain markets may find this product relevant, provided they allocate only a limited portion of their portfolio to such offerings. Performance tracking after launch and the fund house's execution capability will be important factors to monitor.



Unilever and Accenture to Build 40 AI-Powered Digital Twins Across Global Manufacturing Network

Digital Transformation Push: Partnership to Drive Efficiency, Sustainability and Operational Excellence at Scale

Mumbai: Unilever has partnered with Accenture to develop 40 AI-powered digital twins across its global manufacturing network. The initiative aims to create virtual replicas of physical production facilities, enabling real-time simulation, predictive analytics, and process optimisation using artificial intelligence and Internet of Things (IoT) data.

Digital twins will allow Unilever to model entire manufacturing lines, predict equipment failures before they occur, optimise energy consumption, and improve product quality. This technology-driven approach is expected to significantly reduce downtime, lower operational costs, and accelerate decision-making across multiple sites worldwide.

The partnership aligns with Unilever's broader sustainability and digital transformation agenda. By leveraging advanced simulation capabilities, the company aims to reduce waste, lower carbon emissions, and improve resource efficiency key elements of its net-zero and circular economy commitments.

This collaboration highlights the growing importance of digital twins and AI in traditional manufacturing. For Unilever, the move is expected to deliver measurable improvements in productivity and cost efficiency over the medium term, supporting margin expansion.

Investors can view this as part of a larger industry shift towards smart manufacturing

Companies providing AI platforms, industrial IoT solutions, and digital transformation services stand to benefit indirectly from similar adoption trends. Long-term investors tracking the consumer goods and industrial technology themes may find opportunities in firms that successfully integrate advanced technologies into physical operations.

While implementation costs and integration complexities remain watchpoints, the strategic rationale is strong. As more manufacturers adopt digital twins, early movers like Unilever could gain a competitive edge in operational agility and sustainability performance.

Corporates Accelerate Shift to Electric Trucks as Diesel and Logistics Costs Surge

Green Logistics Momentum: Rising Fuel Expenses Push Big Companies Towards Electric Commercial Vehicles for Cost and Sustainability Gains

Udaipur: Major corporates across India are increasingly adopting electric trucks as rising diesel prices and elevated logistics costs force a strategic rethink. Companies in sectors such as FMCG, e-commerce, and manufacturing are piloting or scaling electric commercial vehicles, particularly for intra-city and regional operations.

The shift is driven by the significantly lower operating costs of electric trucks compared to diesel counterparts. With electricity costs being substantially lower than diesel, companies are finding meaningful savings in total cost of ownership over time. Additionally, corporate sustainability goals and upcoming regulatory pressures on emissions are accelerating the transition. While upfront costs of electric trucks remain higher, improving battery

technology, falling battery prices, and expanding charging infrastructure are making the economics more viable. Several large fleet operators have already begun replacing portions of their diesel fleets with electric alternatives.

This trend presents a clear growth opportunity in the electric commercial vehicle segment. Companies involved in manufacturing electric trucks, batteries for heavy vehicles, and charging infrastructure stand to benefit from rising corporate adoption. Long-term investors can consider selective exposure to players with strong capabilities in the electric CV space.

While challenges such as charging infrastructure gaps and suitability for long-haul operations persist, the direction of travel is clear. Rising diesel costs and ESG commitments are likely to sustain

momentum in electric truck adoption over the coming years.



जापानी कंपनी आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ चुंबक इकाई लगाएगी: महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में बड़ा निवेश

रेयर अर्थ क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मिलेगा फायदा

अहमदाबाद: एक जापानी कंपनी आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ चुंबक की विनिर्माण इकाई स्थापित करने जा रही है। यह परियोजना भारत के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दुर्लभ मृदा चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन ऊर्जा टर्बाइनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं। वर्तमान में भारत इन चुंबकों का अधिकांश आयात चीन से करता है। जापानी कंपनी की यह इकाई भारत को आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और आयात निर्भरता कम करने में मदद करेगी। आंध्र प्रदेश में यह परियोजना स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करेगी और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देगी।

यह निवेश रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के तेज विस्तार के साथ इन चुंबकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लंबी अवधि के निवेशक ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और संबंधित सप्लाय चैन से जुड़ी कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं।

सरकार भी महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दे रही है। निवेशक इस क्षेत्र में आने वाले नए प्रोजेक्ट्स और नीतिगत समर्थन पर नजर रखें। जापानी तकनीक के साथ यह इकाई भारत में उच्च गुणवत्ता वाले चुंबक उत्पादन की नींव रख सकती है।



AMCs लॉन्च करेंगे लाइफ साइकल फंड्स: लंबी अवधि की वेल्थ क्रिएशन को बनाएंगे आसान

निवेशकों के लिए सुविधाजनक विकल्प: उम्र के अनुसार ऑटोमैटिक एसेट एलोकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग को मिलेगा नया आयाम

मुंबई: म्यूचुअल फंड कंपनियां (AMCs) लाइफ साइकल फंड्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। ये फंड्स निवेशकों की उम्र या लक्ष्य की समयावधि के अनुसार ऑटोमैटिक रूप से एसेट एलोकेशन बदलते रहेंगे, जिससे लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन आसान हो जाएगा। लाइफ साइकल फंड्स को टारगेट डेट फंड्स भी कहा जाता है। इनमें शुरुआती वर्षों में ज्यादा इक्विटी एलोकेशन होता है, जो समय के साथ धीरे-धीरे डेब्ट की ओर शिफ्ट होता जाता है। उदाहरण के लिए, 30 वर्ष की उम्र वाले निवेशक के लिए ज्यादा इक्विटी और कम डेब्ट, जबकि 55 वर्ष की उम्र वाले के लिए ज्यादा डेब्ट और कम इक्विटी। इससे निवेशक को खुद पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फंड्स मुख्य रूप से रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चे की शिक्षा और अन्य लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। भारत में वित्तीय साक्षरता अभी भी सीमित है और ज्यादातर निवेशक समय पर एसेट

एलोकेशन नहीं बदल पाते, जिससे रिटायरमेंट के समय जोखिम बढ़ जाता है। लाइफ साइकल फंड्स इस समस्या का समाधान पेश कर सकते हैं। लाइफ साइकल फंड्स उन निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं जो खुद पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करना चाहते या जिनके पास पर्याप्त समय नहीं है। ये फंड्स अनुशासित निवेश को बढ़ावा देंगे और व्यवहार संबंधी गलतियों को कम करेंगे। हालांकि, ये फंड्स हर निवेशक की व्यक्तिगत जोखिम क्षमता के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज्ड नहीं होते। निवेशक अपनी उम्र, जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्य के अनुसार सही लाइफ साइकल फंड चुनें। लंबी अवधि के निवेशक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए इन फंड्स पर विचार कर सकते हैं।

AMCs द्वारा इन फंड्स के लॉन्च से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को नया उत्पाद मिलेगा और रिटेल निवेशकों को सरल विकल्प उपलब्ध होगा। निवेशक NFO के दौरान या बाद में इन फंड्स का मूल्यांकन करें और अपनी समग्र वित्तीय योजना के साथ जोड़कर निवेश का निर्णय लें।



जायडस लाइफसाइंसेज ने पूरा किया असर्टियो का अधिग्रहण: अमेरिकी बाजार में मजबूत उपस्थिति

निवेशकों के लिए सकारात्मक: पोर्टफोलियो विस्तार और यूएस फुटप्रिंट बढ़ने से लंबी अवधि की ग्रोथ संभावनाएं

अहमदाबाद: जायडस लाइफसाइंसेज ने अमेरिकी फार्मा कंपनी असर्टियो (Assertio) का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह सौदा जायडस की अमेरिकी बाजार में उपस्थिति को और मजबूत करेगा और कंपनी के स्पेशियलिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को विस्तार देगा। असर्टियो मुख्य रूप से दर्द प्रबंधन और माइग्रेन से जुड़ी दवाओं में सक्रिय है। इसके प्रमुख उत्पाद जैसे कैम्बिया और जिप्सोर माइग्रेन और अन्य दर्द संबंधी इलाज में इस्तेमाल होते हैं। जायडस के लिए यह अधिग्रहण जेनेरिक दवाओं से आगे स्पेशियलिटी और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ने की रणनीति का हिस्सा है। इससे कंपनी को अमेरिका में तैयार बाजार, स्थापित ब्रांड और मौजूदा बिक्री नेटवर्क मिलेगा। अधिग्रहण से जायडस को तत्काल राजस्व वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही दोनों कंपनियों के बीच क्रॉस-सेलिंग और नए उत्पाद विकास के अवसर भी खुलेंगे। जायडस पहले से ही अमेरिका में जेनेरिक दवाओं

का मजबूत कारोबार चला रही है और यह सौदा उसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। यह अधिग्रहण जायडस लाइफसाइंसेज के शेयरधारकों के लिए सकारात्मक विकास है। अमेरिकी बाजार में स्पेशियलिटी प्रोडक्ट्स की मौजूदगी से कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल में सुधार आने की संभावना है। लंबी अवधि के निवेशक फार्मा सेक्टर में इनॉर्गेनिक ग्रोथ करने वाली कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि अधिग्रहण के बाद एकीकरण की चुनौतियां और नियामकीय अनुपालन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। निवेशक जायडस के आने वाले तिमाही नतीजों में असर्टियो के योगदान और समग्र मार्जिन पर नजर रखें। यह सौदा भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा अमेरिका में स्पेशियलिटी सेगमेंट में बढ़ते निवेश को दर्शाता है। लंबी अवधि में ऐसे अधिग्रहण सेक्टर को मजबूत कर सकते हैं।



अडाणी ग्रीन ऑफशोर बॉरोइंग के जरिए जुटा सकती है 1 अरब डॉलर: अमेरिकी सेटलमेंट के बाद बाजार में वापसी

रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को मिलेगा बल, वैश्विक पूंजी बाजार में भरोसा लौटा

मुंबई: अडाणी ग्रीन एनर्जी अमेरिकी सेटलमेंट के बाद ऑफशोर मार्केट से 1 अरब डॉलर तक की फंडिंग जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी इस राशि का उपयोग अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार और कर्ज पुनर्गठन के लिए कर सकती है। अमेरिकी नियामकों के साथ सेटलमेंट के बाद अडाणी समूह की कंपनियों ने धीरे-धीरे बाजार में विश्वास बहाल करने की कोशिश की है। अडाणी ग्रीन का यह कदम दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक अब फिर से कंपनी पर भरोसा जता रहे हैं। भारत सरकार के नेट-जीरो लक्ष्यों को देखते हुए अडाणी ग्रीन की परियोजनाओं का विस्तार राष्ट्रीय महत्व का है।

यह विकास अडाणी ग्रीन और समग्र रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए सकारात्मक है। ऑफशोर फंडिंग से कंपनी को सस्ती दरों पर पूंजी मिलने की संभावना है, जिससे परियोजनाओं की लागत कम होगी और रिटर्न बेहतर हो सकता है। निवेशक अडाणी ग्रीन के शेयरों पर नजर रख सकते हैं, लेकिन कर्ज के स्तर और प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन पर ध्यान देना जरूरी है। लंबी अवधि के निवेशक हरित ऊर्जा थीम पर फोकस कर सकते हैं। भारत में सोलर और विंड एनर्जी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे इस सेक्टर में अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। निवेशक वैश्विक ब्याज दरों और कंपनी के फंड रेजिंग प्लान पर नजर रखें।



Trackk Enters Broking as Wealthtech Startups Target Gen Z Investors

Digital Broking Push: Startups Eye Young Investors with Tech-Driven Platforms and Low-Cost Investing Options

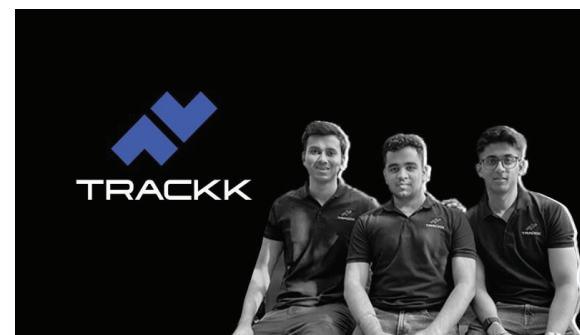
Gurugram: Wealthtech startup Trackk has entered the stock broking business, joining a growing list of fintech players aggressively targeting Gen Z investors. The move reflects a broader industry shift as startups look to capture the next generation of retail investors who are increasingly active in equities, mutual funds, and digital assets.

Gen Z investors, typically aged between 18 and 28, prefer mobile-first platforms, gamified experiences, low-cost trading, and easy access to research and portfolio tools. Trackk aims to differentiate itself through technology-driven features and seamless user experience.

This trend signals strong long-term potential for the fintech and wealthtech sector. As Gen Z enters the workforce and begins building wealth, demand for digital investment platforms is expected to rise significantly. Companies that can combine low-cost broking with strong technology and financial education tools are likely to gain market share.

Investors tracking this space should focus on platforms demonstrating consistent user growth, improving unit economics, and strong regulatory compliance. While competition remains intense, the structural shift towards digital investing and rising retail

participation in Indian markets provides a favourable backdrop for well-executed wealthtech players over the next 5–7 years.



मध्य प्रदेश में युवा उद्यमियों को ₹360 करोड़ की मदद: मोहन यादव सरकार का बड़ा कदम

स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा बल, युवा उद्यमिता से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए ₹360 करोड़ की सहायता राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में यह कदम राज्य में युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह सहायता मुख्य रूप से स्टार्टअप, युवा उद्यमियों और छोटे उद्योगों को दी जाएगी। इसमें सब्सिडी, ब्याज मुक्त ऋण, कौशल विकास और मार्केट लिंकेज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना करना है। इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।

यह घोषणा मध्य प्रदेश के स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत है। युवा उद्यमियों को मिल रही वित्तीय सहायता से नए बिजनेस मॉडल और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। लंबी अवधि के निवेशक स्टार्टअप इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी, मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर ध्यान दे सकते हैं।

राज्य सरकार की यह पहल निवेश के माहौल को और बेहतर बनाएगी। निवेशक युवा उद्यमियों द्वारा शुरू किए जा रहे नए प्रोजेक्ट्स और उनके प्रदर्शन पर नजर रखें। मध्य प्रदेश में युवा उद्यमिता को मिल रहा सरकारी समर्थन राज्य की अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में मजबूत आधार प्रदान करेगा।



Gimi Michi Raises \$1 Million Led by India Quotient: Korean Food Startup Gains Momentum in India

Ethnic Cuisine Wave: VC Interest in Korean Food Signals Rising Demand for Global Flavours Among Indian Consumers

Bengaluru: Korean food startup Gimi Michi has raised \$1 million in a funding round led by India Quotient. The fresh capital will be used to expand its product portfolio, strengthen distribution, and scale operations across key Indian cities.

Gimi Michi offers a range of Korean food products, including ready-to-cook meals, sauces, and snacks, catering to the growing appetite for Korean cuisine among Indian consumers. The popularity of K-pop, K-dramas, and Korean culture has

significantly boosted demand for authentic Korean flavours in India, creating a niche but fast-growing market segment.

This funding round highlights increasing investor interest in ethnic and international food startups. As Indian consumers, especially younger demographics, experiment more with global cuisines, startups offering convenient and authentic products stand to benefit. The deal also reflects India Quotient's continued focus on consumer

and foodtech opportunities. Long-term investors can view the ethnic food and premium convenience food segment as an emerging theme with multi-year growth potential. While competition in the broader food space remains high, differentiated players with strong product quality and brand building can create meaningful value. Investors should track repeat purchase rates, distribution expansion, and margin improvement in such startups.

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24013	24431	24270	24141	23980	23851	23690	23561
BANK NIFTY	57686	58698	58251	57969	57522	57240	56793	56511
SENSEX	76803	78835	78164	77483	76812	76131	75460	74779
FINNIFTY	26431	26832	26672	26552	26392	26272	26112	25992
MIDCAP	14619	14946	14792	14705	14551	14464	14310	14223
ACC	1346	1401	1387	1367	1353	1333	1319	1299
AXISBANK	1360	1410	1394	1377	1361	1344	1328	1311
ABCAPITAL	373	393	385	379	371	365	357	351
BHARTIARTL	1905	2040	1978	1941	1879	1842	1780	1743
BHEL	417	477	450	434	407	391	364	348
BIOCON	415	441	432	424	415	407	398	390
BEL	427	463	448	437	422	411	396	385
CDSL	1370	1579	1488	1429	1338	1279	1188	1129
DATAPATTERN	4818	5690	5323	5070	4703	4450	4083	3830
ESCORTS	2831	3015	2960	2895	2840	2775	2720	2655
EICHERMOTOR	7650	8173	7921	7785	7533	7397	7145	7009
FEDERAL BANK	324	340	333	328	321	316	309	304
GRINFRAPROJECT	892	960	937	914	891	868	845	822
HDFCBANK	781	824	814	797	787	770	760	743
HCLTECH	1130	1253	1213	1172	1132	1091	1051	1010
HINDUNILVR	2202	2310	2267	2235	2192	2160	2117	2085
HAL	4395	4801	4643	4519	4361	4237	4079	3955
HYUNDAI	1979	2140	2100	2039	1999	1938	1898	1837
IOC	144	152	150	147	145	142	140	137
ICICIBANK	1348	1404	1383	1366	1345	1328	1307	1290
INFY	1054	1266	1215	1134	1083	1002	951	870
ITC	294	303	299	296	292	289	285	282
KOTAKBNK	400	421	416	408	403	395	390	382
LICHOUSING	550	592	581	566	555	540	529	514
LT	4210	4375	4310	4260	4195	4145	4080	4030
LUPIN	2353	2488	2422	2387	2321	2286	2220	2185
MARUTI	13425	14414	14188	13806	13580	13198	12972	12590
M&M	3080	3253	3210	3145	3102	3037	2994	2929
MGL	1210	1378	1304	1257	1183	1136	1062	1015
MAZGAONDOC	2525	2718	2644	2584	2510	2450	2376	2316
PFC	431	452	444	438	430	424	416	410
RECLTD	356	378	371	364	357	350	343	336
RELIANCE	1312	1367	1353	1332	1318	1297	1283	1262
SBIN	1036	1091	1069	1052	1030	1013	991	974
SUNPHARMA	1840	1908	1875	1858	1825	1808	1775	1758
SHRIRAMFINANCE	1001	1045	1031	1016	1002	987	973	958
TITAN	4415	4718	4580	4497	4359	4276	4138	4055
TCS	2136	2392	2311	2224	2143	2056	1975	1888
TATAMOTORS	359	446	427	393	374	340	321	287
UPL	609	649	638	624	613	599	588	574
VALIENT	291	358	340	315	297	272	254	229
WIPRO	181	196	190	186	180	176	170	166

छोटे उद्योगों को मिला बड़ा सहारा: ढाई साल में ₹3,723 करोड़ इंसेंटिव, तीन गुना ज्यादा मदद

एमएसएमई सेक्टर को मजबूत सरकारी समर्थन, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति

भोपाल: मध्य प्रदेश में छोटे उद्योगों (एमएसएमई) को ढाई साल में ₹3,723 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया गया है। यह राशि पिछले ढाई साल की तुलना में तीन गुना ज्यादा है। सरकार की इस पहल से राज्य के छोटे उद्योगों को बड़ा सहारा मिला है।

यह सहायता मुख्य रूप से नए उद्योग लगाने, पुराने उद्योगों के विस्तार, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रोजगार सृजन के लिए दी गई है। इंसेंटिव में ब्याज सब्सिडी, पावर सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इससे छोटे उद्योगों को लागत कम करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिली है। खासकर पीथमपुर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में इसका सकारात्मक असर देखा जा रहा है।

यह आंकड़ा एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत उत्साहजनक है। सरकारी इंसेंटिव बढ़ने से नए निवेश आकर्षित होंगे और मौजूदा इकाइयों का विस्तार होगा। लंबी अवधि के निवेशक मैनुफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग और सर्विस सेक्टर पर ध्यान दे सकते हैं।

राज्य में एमएसएमई की मजबूत ग्रोथ से सप्लाय चैन और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। निवेशक सरकारी योजनाओं की प्रगति, इंसेंटिव के उपयोग और नए उद्योगों की स्थापना पर नजर रखें। मध्य प्रदेश में छोटे उद्योगों को मिल रहा मजबूत समर्थन राज्य की औद्योगिक विकास यात्रा को और तेज करेगा।



Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.